



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 29, 1985/चैत्र 8, 1907

No. 159]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 29, 1985/CHAITRA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बलपूर्वक संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 मार्च, 1985

आदेश

का. आ. 275(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./85 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 320(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./79 तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में मर्म अपोलो जिप्पर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, कलकत्ता नामक सम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और सचिव, बन्द और मरण उद्योग विकास विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार का, जिसे अब सचिव, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1985 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये

ऐसे जारी रहने के लिये, समय-समय पर निवेश जारी किये थे । [देखिए भारत सरकार के मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 246(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 25 मई, 1982, सं. का. आ. 832(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./82, तारीख 24 नवम्बर, 1982, सं. का. आ. 385 (अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./83, तारीख 31 मई, 1983, सं. का. आ. 872(अ)/18कक/आई.डी.आ.ए./83, तारीख 30 नवम्बर, 1983, सं. का. आ. 472(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 28 जून, 1984, और सं. का. आ. 975 (अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984] ।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे ,

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश होती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहगा ।

[फा. सं. 2(23)/80-सी. य. एम.]

ए. पी. मरबन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY AND COMPANY
AFFAIRS**

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th March, 1985

ORDER

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the whole of the Industrial Undertaking known as Messrs Apolly Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking :

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had

issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1985 [vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982, S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82 dated the 24th November, 1982, S.O. 385(E)|18AA|IDRA|83, dated the 31st May, 1983, S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83 dated the 30th November, 1983, S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984, and S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984];

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a period upto and inclusive of the 31st March 1986;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA, read with the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulations) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1986.

[File No. 2(23)|80-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.